

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 10 सितम्बर 2025 बुधवार

सम्पादकीय

नेपाल में तख्ता पलट के संकेत

पड़ोसी देश नेपाल में वामपंथी विचारधारा के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के तख्ता पलट की उम्मीद काफी बढ़ गई है। ओली के मंत्री और सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। आम जनता के गुस्से को माप कर प्रधानमंत्री ओली के साथ-साथ उनके समर्थन वाले कई नेताओं के विदेश जाने की खबरें भी आ रही हैं। मौजूदा हालात में अगर ओली सरकार गिरती है, तो सबसे पहले सत्ता में आने का रास्ता नेपाली कांग्रेस जैसी मध् यमार्गी, लोकतांत्रिक विचारधारा वाली पार्टी के लिये सबसे अधिक खुलेगा। नेपाली कांग्रेस संसद की सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि सीपीएन-यूएमएल (ओली की पार्टी) दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इनके बाद तीसरी ताकत माओवादी केंद्र है, जो प्रगतिशील मगर ओली की तुलना में अधिक विविध गठबंधन की ओर झुकी रही है। ओली के नेतृत्व में मंत्रीमंडल में शामिल सहयोगी दलों ने पहले भी समर्थन वापस लिया है, इसलिए सत्ता परिवर्तन का रास्ता पहले संसदीय दल के बीच मेल-मिलाप, फिर बहुमत परीक्षण के जरिये तय होगा। नई सरकार के लिये गठबंधन जरूरी है, जिसमें कांग्रेस, माओवादी केंद्र और क्षेत्रीय दल प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है।

ओली सरकार की स्थिरता एक बार फिर बड़े संकट में फंस गई है, इसका ट्रिगर हालिया आंदोलन बना, जिसमें भ्रष्टाचार, भेदभाव और सोशल मिडिया नियंत्रण के खिलाफ युवाओं ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर कर विरोध किया। इन प्रदर्शनों को दबाने के दौरान पुलिस की फायरिंग में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद सरकार की साख और समर्थन तेजी से गिरा है। साथ ही ओली कैबिनेट से इस्तीफा का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले गृह मंत्री रमेश लेखक (नेपाली कांग्रेस) ने इस्तीफा देकर नैतिक जिम्मेदारी ली। इसके बाद कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी (नेपाली कांग्रेस) ने भी सरकार की नीतियों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफे बताते हैं कि सरकार के सामने बड़ी सिंघासी चुनौती है और बहुमत खोने का संकेत फिर है।

नेपाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के कई निशाने और असर भारत पर भी सीधे पड़ते हैं। नई सरकार का गठन भारत और चीन दोनों के लिये कूटनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाएगा। भारत पारंपरिक रूप से नेपाल की लोकतांत्रिक, संवैधानिक व्यवस्था को समर्थन देता रहा है और बार-बार राजनीतिक स्थिरता का प्रश्नरूप रखा है। नेपाल में वामपंथी हुकूमत आमतौर पर चीन के करीब दिखती हैं और भारत के साथ कई अहम समझौतों को ओझल कर देती हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस जैसे दल खुलकर भारत-नेपाल सांस्कृतिक, राजनयिक, व्यापारिक रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। अगर ओली सरकार गिरती है और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आता है, तो भारत-नेपाल संबंधों के सज्ज होने, आपसी व्यापार बढ़ने और सीमाई विवादों के कम होने की संभावना कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। वहीं, ओली द्वारा लागू कट्टर राष्ट्रवाद जो चीन के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिशों में झलकता रहा उसमें ब्रेक लग सकता है।

नेपाल के हालिया राजनीतिक अस्थिरता के भारत पर प्रभाव को तीन पहलुओं में समझा जा सकता है। पहला, भारत नेपाल में स्थिरता चाहता है ताकि मध् य, सीमा विवाद और पारगमन व्यापार को लेकर सहयोग बढ़ सके। अस्थिर सरकारों का कारण अक्सर समझौते टल जाते हैं या नए सिर से कूटनीति की जरूरत पड़ती है। दूसरा, ओली की वामपंथी सरकार ने भारत के खिलाफ राष्ट्रवादी बोल, सीमाई मुद्दों पर चीन के पक्ष में झुकाव और आंतरिक राजनीति में बाहरी (खासकर भारतीय) दखल का आरोप बार-बार लगाया। सत्ता परिवर्तन से भारत के लिए एक संवेदनशील व्यवहारिक सहयोगी सामने आ सकता है। तीसरा, चीन के दबाव और नेपाल की आंतरिक राजनीति में सैन्य व आतंरिकरण सहयोग के मुद्दे पर भारत सावधान रहता है। नई सरकार बनने के बाद भारत-नेपाल के कूटनीतिक संतुलन को साधने की कोशिश संभव है। ओली सरकार में जो मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, उनमें गृह मंत्री रमेश लेखक और कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी (दोनों नेपाली कांग्रेस) के नाम सामने आ चुके हैं। दोनों ने व्यापक विरोध-प्रदर्शन, विपक्षी दलों के दबाव और अंतरिम बंदरता व जवाबदेही के अभाव को लेकर इस्तीफा दिया है। इनके अलावा भी गंभीर असंतोख के संकेत मिल रहे हैं।

नेपाल में नई पीढ़ी का असंतोख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नीची र्थी की मांग है, जिससे सरकार का जायाभार कमजोर हुआ है। ओली सरकार के जाने के बाद केंद्र में लोकतांत्रिक, लोकतत्वाणकारी एजेंडा रखने वाली पार्टियों का दबदबा बढ़ सकता है, जिससे भारत-नेपाल संबंधों में नया संचार और क्षेत्रीय संतुलन संभव है। किंतु सेट बैक यह रहेगा कि बार-बार सिंघासी उठावटने नेपाल की आंतरिक प्राकृतिक व मानववी संसाधनों को भी और लंबा खींच सकता है, जिसका सीधा असर भारत-नेपाल के सीमाई इलाकों, प्रवासी कामगारों और सांस्कृतिक रिश्तों पर पड़ेगा। इसलिए घटनाक्रम पर भारत की दोतरफा कूटनीतिक सक्रियता बढ़ना तय है।

जीएसटी सुधार, जीप-टेम्पो की यादें, घोषणा से जमीन तक का सफर



—अशिश कुमार यादव—

मेरा घर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसा हुआ है। बचपन से ही यह राजमार्ग मेरी आँखों के सामने केवल कंक्रीट और डामर की सड़क नहीं रहा, बल्कि एक जीवत धारा की तरह रहा। सुबह होते ही गाड़ियों की आवाज पर घर गूँज उठता। यात्री टेम्पो में चढ़ते, जीपों में बैठते, और कभी-कभी बसों में भीड़ लग जाती। मेरे बचपन का सबसे बड़ा रोमांच इन गाड़ियों को आते-जाते देखना ही था। यह दृश्य केवल यातायात का नहीं बल्कि उस दौर की अर्थव्यवस्था और समाज की धड़कन भी था। 90 के दशक में सबसे लोकप्रिय तीन-पहियों वाला टेम्पो थी। इसका असली नाम हेनसेट टेम्पो था, जिसे जर्मनी की कंपनी ने विकसित किया और भारत में बाजार ने उत्पादन शुरू किया। आम लोग इसे 'फूड वाली गाड़ी', 'कोआ गाड़ी'



या 'गणेशजी' कहते थे। ये टेम्पो और जीप गाँव और कस्बों के बीच आवाजाही आसान बनाते। छोटे किसान अपना अनाज, व्यापारी अपना लवजरी, हाकिमकार वस्तुएँ, 40 प्रतिशत में अलग से रखी गई हैं। कागज पर कदम साहसिक है, कारोबारियों और उम्पकोंओं के लिए आसान। लेकिन सवाल वही है, क्या राहत जनता तक पहुँचेगी?

आज जब जीएसटी सुधारों की चर्चा सुनता हूँ, वही टेम्पो-जीप की यादें ताजा हो जाती हैं। सरकार ने

कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए चार स्लैब घटाकर दो प्रमुख दरों (5 और 18) पर है। आवश्यक वस्तुएँ शुल्क प्रतिशत और लवजरी, हाकिमकार वस्तुएँ, 40 प्रतिशत में अलग से रखी गई हैं। कागज पर कदम साहसिक है, कारोबारियों और उम्पकोंओं के लिए आसान। लेकिन सवाल वही है, क्या राहत जनता तक पहुँचेगी?

सरकार ने काँपियों और कितानों पर 5 टैक्स तय किया, संदेश दिया कि शिक्षा का बोझ हल्का होगा। लेकिन कागज, उद्योग का मुख्य आधार, अब 12 के स्लैब से निर्धारित 18 में है। उत्पादन लागत बढ़ी, किसान जस की तस। जैसे कि जीजल का दाम घटने के बाद भी

टेम्पो का किराया जस का तस रहता था, वैसे ही अब काँपों की कीमतें नहीं घटेगी। नीति और नीयत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जमीनी असर तभी होगा जब हर स्तर पर संतुलन रहे। यदि कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स और तैयार माल पर कम, तो इसे इनवर्टेड झुट्टी स्ट्रक्चर कहते हैं। इससे छोटे उद्योग और एम्पएसएमई सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पहले स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 जीएसटी वसूला जाता था। यदि कोई 10,000 रुपये देता, तो 1,800 रुपये टैक्स चुकाने पड़ते। हाल ही में इसे हटा दिया गया। सतही राहत दिखती है, लेकिन कंपनियों के इनपुट से क्रेडिट खत्म होने से प्रीमियम बढ़ने

की आशंका है। जैसे टेम्पो-जीप का किराया घटता नहीं था, वैसे ही अब बीमा प्रीमियम में भी जनता को सीधे राहत नहीं मिल रही। मीडिया रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि ऑटो डीलर्स वित्तीय दबाव में हैं। टेक्सटाइल उद्योग और एफएमसीडी कंपनियों पुराने स्टॉक की लागत बढ़ने जैसी चुनौतियों से जूझ रही हैं। कंपनियों पर नए स्लैब को समायोजित कर रही हैं, लेकिन इसका लाभ उम्पकोंओं तक पहुँच रहा है या नहीं, यह सवाल खड़ा है। जैसे टेम्पो-जीप ने गाँव और शहर के बीच आवाजाही आसान की थी, वैसे ही अब इन सुधारों का असर उम्पकोंओं तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन लाभ अब भी सीमित है। टेम्पो-जीप वाली यादों का संदेश आज भी प्रसरित है। नीति और नीयत घोषणा भले ही बेहतर हों, असली राहत तभी होती है जब जनता के जेब पर असर दिखे। यह केवल आंकड़ों या प्रेस कॉन्फ्रेंस से मापा नहीं जा सकता। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन किसानजन की ईमानदारी ही असली कसौती है। नीति को जमीन तक पहुँचाने के लिए निगरानी, संतुलन और व्यावहारिक समझ जरूरी है। यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनियों टैक्स छूट का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुँचें। न कि केवल अपने मुनाफे या वित्तीय लक्ष्योपार्जन के लिए। इसमें लापरवाही, सरकारी से अलगाव है कि वह केवल नीति बनाने

तक सीमित न रहे। इनवर्टेड झुट्टी स्ट्रक्चर खत्म करें, कंपनियों पर निगरानी रखें, और उम्पकोंों तक वास्तविक राहत पहुँचाने की गारंटी दें। तभी नीतियों केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा न रहकर जनता के जीवन में बदलाव बनेगी। फिलहाल स्थिति यह है कि सुधारों का राजनीतिक श्रेय सरकार को और वित्तीय लाभ कंपनियों, बिजोलियों व डीलरों को मिल रहा है। आम उम्पकोंों अब भी उसी हाल में हैंकुत्ते से कभी डीलजल सत्ता होने पर टेम्पो-जीप का किराया नहीं घड़ा। सवारी अब भी पूरा किराया चुकाने की है, राहत सिर्फ घोषणा में दर्ज है। असली सुधार तब होगा जब घोषणा से जनता तक असली जनता की जेब में दिखेगा। इस पूरी प्रक्रिया का संदेश होता है कि नीति और नीयत के बीच वास्तविक अंतर का फासला अभी भी बरकरार है। यदि शिक्षा हो, बीमा हो, ऑटोमोबाइल या एफएमसीडी, जनता वही अनुभव करेगी कि ईकुवोपाता होने है, लेकिन वास्तविक राहत सीमित या नगण्य रहती है। यही वह सीख है जो टेम्पो और जीप ने मुझे बचपन में दी थी। ऊपर से कितनी भी एतान हो, असली राहत तब होती है जब जमीन पर, जब किराया देते, कीमतें कम हों, और नीति का असर सीधे आम आदमी तक पहुँचे। यदि जीएसटी सुधार का लाभ केवल घोषणा और आंकड़ों तक सीमित रह गया, तो यह केवल शब्दों की राहत भर होगी, वास्तविक नहीं।

नेपाल का आनलाइन लॉकडाउन, आजादी पर सवाल



— डॉ प्रियंका सौरभ—

नेपाल जैसे छोटे लोकतांत्रिक देश ने हाल ही में ऐसा बड़ा निर्णय लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सरकार ने 26 सप्ताह मिडिया और संदेश मंचों पर अनामक रोक लगाने का आदेश दिया। इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सबसे लोकप्रिय मंच शामिल हैं। यह फैसला जितना अचानक लिया गया, उतना ही गहरी बहस भी शुरू कर दी कि क्या यह कदम नागरिक अधिकारों पर हमला है या देश की डिजिटल सुखा के लिए जरूरी था। सरकार का कहना है कि सोशल मिडिया कंपनियों को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वे अपनी मंचों में अनामक न्यायिक कार्यालय खोलें, प्रतिनिधिक नियुक्त करें और शिकायत निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लेकिन कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया। सरकार के अनुसार, इस कारण अचानक, भ्रामक खबरें और साक्षर अपराधों से बड़ रहे थे। इसे रोकने के लिए ही यह बड़ा कदम उठाया गया।

लेकिन इस फैसले का विरोध भी तेजी से हो रहा है। पत्रकार संगठन, मानवाधिकार समूह और आम नागरिक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। उनका तर्क है कि सोशल मिडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह अब नागरिकों की आवाज और लोकतंत्र का आधार बन चुका है। इस इतने बड़े स्तर पर मंच बंद कर दिए जाएंगे, तो जनता की संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गहरा असर पड़ेगा।

नेपाल में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य विदेशों में काम कर रहे हैं। उनके लिए व्हाट्सएप और फेसबुक ही परिवार से जुड़े रहने के सबसे आसान माध्यम हैं। इस प्रक्रिया से उनका रोजमर्रा की जिंदगी कठिन हो जाएगी। यही नहीं, छोटे व्यापारी और ऑनलाइन कारोबार करने वाले लोग भी सोशल मिडिया के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचते थे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर विज्ञापन देकर वे अपने उत्पाद बेचते थे। अब यह सब प्रभावित होगा। हजारों सामाजिक निर्माता और यूजर्स, जो सोशल मिडिया से अपनी रोजी-रोटी बना रहे थे, अचानक बेरोजगार होने की कगार पर पहुँच जाएंगे। युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है, बल्कि आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि डिजिटल रोजगार पर भी बड़ा झटका है।



नेपाल सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विपक्ष इसे तानाशाही कदम मान रहा है। उनका कहना है कि सरकार आलोचना और सवालों से डर रही है, इसलिए उत्पन्न सोशल मिडिया पर रोक लगा दी। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज में है। जब उस आवाज को दबाया जाता है, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नेपाल की छवि प्रभावित होगी। निवेशक और उद्योगपति कंपनियों को बड़ा सौचगी कि नेपाल का डिजिटल माहौल निवेश और सुवर्धित नहीं है। इससे निरंतर और साझेदारी पर असर पड़ेगा। पंडित भी नाबुल हो सकते हैं, क्योंकि आज यात्रा, संचार और जानकारी का बड़ा हिस्सा सोशल मिडिया पर आधारित है।

सरकार का तर्क बिल्कुल गलत नहीं है। सोशल मिडिया पर अपमान, फूँट खरबें और साक्षर अपराध तेजी से फैल रहे हैं। इससे सामाजिक तनाव और हिंसा भी भड़क सकती है। सरकार को यह कह है कि वह नागरिकों की सुखा सुनिश्चित करे और कंपनियों को जिम्मेदार बनाए। लेकिन समस्या का हल सीधे मंचों को बंद करना नहीं होगा चाहिए।

दुनिया के कई देशों ने सोशल मिडिया कंपनियों पर नियम लागू किए हैं। भारत ने 2021 में नए सुचना प्रोधानियों की नियम बनाए, जिनमें कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना और सामग्री पर दुरुत कार्रवाई करना अनिवार्य किया गया। यूरोपियन संघ ने भी डिजिटल सेवा कानून लागू किया। लेकिन कहीं भी इसे तब तक पूर्ण प्रतिक्रि नहीं लगाया गया। नेपाल का कदम इसलिए कठोर और जल्दबाजी बना लगता है।

समाधान यह है कि सरकार कंपनियों से बातचीत करे, उन पर जुर्माना लगाए और नियमों का पालन करने के लिए दबाव बनाए। जनता की आवाज को पूरी तरह रोकना सही रास्ता नहीं है। हम न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है बल्कि जनता और सरकार के बीच अस्थिरता भी बढ़ाएगा।

महिय में नेपाल को संतुलन की राह चुननी पड़ेगी। उसे समझना होगा कि सोशल मिडिया अब केवल तकनीकी साधन नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इसे बंद करना लोगों की

स्वतंत्रता और संवाद दोनों पर मोट है। बेहतर होगा कि सरकार कंपनियों में सही कदम नियमों के दायरे में रखे, लेकिन नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुवर्धित न हो। लोकतंत्र की असली ताकत जनता का भरपूर है। यह मनोना तभी बनता है जब सरकार जनता से संवाद करेगी, न कि उसकी आवाज को दबाएगी। नेपाल को चाहिए कि वह अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे और ऐसा रास्ता अपनाए जिससे कानून का पालन भी हो और नागरिकों की स्वतंत्रता भी सुवर्धित रहे। यही सही लोकतांत्रिक समाधान है।

नेपाल की यह घटना पूरे विश्व के लिए भी सुनिहा है। यह दिखाती है कि डिजिटल दुनिया में नियमों और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। एक ओर सुखा, अनामकों और अपराधों पर नियंत्रण की जरूरत है, तो दूसरी ओर जनता की अभिव्यक्ति और सवात की स्वतंत्रता का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। यदि यही संतुलन मिल जाता है, तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा और डिजिटल दुनिया का लाभ सभी को मिलेगा।

नेपाल के निर्णय ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारें डिजिटल दुनिया में सही कदम उठाने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इन जिम्मेदारों का मतलब जनता की आवाज पर अंकुश लगाना नहीं होगा चाहिए। यह लोकतंत्र न नागरिकों की स्वतंत्रता सवात है। इसलिए नेपाल को चाहिए कि वह कानून की कठोरात और लोगों की स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाए और सोशल मिडिया को केवल प्रतिक्रिया के साधन न बने दे। अतः यह निर्णय एक चेतावनी भी है कि सोशल मिडिया का महत्व अब केवल मनोरंजन या सुचना तक सीमित नहीं है। यह लोकतंत्र, रोजगार, सामाजिक संवाद और वैश्विक पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। इसे सही ढंग से निभारित करना, नियम लागू करना और नागरिकों की आवाज सुवर्धित रखना ही मविध की दिशा है।नेपाल को चाहिए कि वह इस निर्णय का पुनर्विचार करे और ऐसा समाधान निकाले जो कानून का पालन सुनिश्चित करे, अनामकों और साक्षर अपराध पर रोक लगाए, और साथ ही जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सुवर्धित रखे। यही लोकतंत्र की सच्ची ताकत है।

नये सन्दर्भों में बदलते ट्रंप के सुर

—संतोष कुमार भार्गव—

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़ गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि भारत किसी भी देश के सामने झुकने वाला नहीं है। पूर्व भारतीय राजनयिक के.पी. फैबियन ने ट्रंप के पोस्ट और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया का मतलब समझाया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अब समझ आ रहा है कि उनकी आक्रामक व्यापारिक धमकियां भारत साबित हो रही हैं। हाल में ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों को श्वेत-बहुत खास रास्ता बनाया है। यह एक समझा वाला देश है। भारत किसी भी देश का पिछलगू नहीं बन सकता। भारत सबसे साथ दोस्ती चाहता है। व्यापार करना चाहता है। लेकिन, भारत किसी की तानाशाही नहीं मानेगा। यह बात ट्रंप की ओर से भारत-अमेरिका संबंधों पर नरम रख अपनाने के बाद आई है। ट्रंप ने इन संबंधों को श्वेत खास रास्ता बनाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती की बात भी कही।

लेकिन उनकी सरकार ने भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही भारत के रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ भी थोपा है। इससे रूस टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। 50 फीसदी टैरिफ के बाद जिस तरह का तनाव बन गया था, अब ट्रंप के बदलते सुर को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों पर तनाव की बर्फ पिघल रही है। हालांकि टैरिफ पर अभी कोई आधिकारिक बात नहीं हुई है, लेकिन तनाव कम होता दिख रहा है। दोनों ही नेताओं के ताजा बयान इस बात के संकेत हैं कि कि दोनों देशों के बीच बिगड़ रिश्ते धीरे-धीरे सामान्य हो सकते हैं। आधों का दा है कि फिलहाल अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाया गया 50 प्रतिशत टैक्स जारी है।

वर्तमान में विश्व के तमाम देशों से व्यापार और राजनीतिक संबंध रखना सबके लिए जरूर है। बात अगर भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों की कि जाए तो एप्पल ने भारत से 67,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। 'मेजने' ने 40,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। 'गूगल' ने 22-23,000 करोड़ रुपए बनाए हैं और 'मेटा' ने भी लगभग इतनी ही कमाई की है। ये सभी अमेरिकी कंपनियां हैं जो भारत उनका सबसे बड़ा बाजार हैं। भारत से इनके फॉर्म भी सड़कें हो अथवा थ्यापिड होने की प्रक्रिया में होंगे। ऐसी कड़ और अमेरिकी कंपनियों होंगे, जो भारत में व्यापार कर रही हैं और मेटा मुनाफा कूट रही है। इन कंपनियों



के सबसे अधिक ग्राहक और उद्योगपतों की यादें हैं। सवाल यह है कि ट्रंप को मुनाफा अमेरिका में ही जा रहा है।

राष्ट्रपति ट्रंप अब भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं? चूंकि अमेरिकी कंपनियां भारत में उत्पादन कर रही हैं और माल अमेरिकी बाजार में आ रहे हैं, क्या राष्ट्रपति ट्रंप इन उत्पादों पर भी 50 फीसदी टैरिफ थोपेंगे? अतः ट्रंप हरीजो टैरिफ पर सफाई दे रहे हैं। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप 100 दिनों के अंतराल में टैरिफ पर पुनर्विचार कर अपने फैसले को वापस ले सकते हैं। लिहाजा उन्होंने स्वास्व्य अलावत से आग्रह किया है कि वह टैरिफ मामले पर थ्याशीघ्र सुनवाई कर उसे बंद कर दें। अलावत नवंबर माह में सुनवाई शुरू करेगी, यह पहले से ही तय है।

राष्ट्रपति ट्रंप इसलिए भी चिंतित हैं, क्योंकि दुनिया दो ब्लॉकों में बंटी जा रही है और अमेरिका को 'श्रीत युद्ध' एक बार फिर शुरू होने की आशंका है। अमेरिका की ताकत भी बंटी जा रही है। अब देश अमेरिका की 'दादगीरी' मानते रहने को तैयार नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी मंत्री और भी भारत को अपना 'परम मित्र' मानते हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि देश के राष्ट्रपतियों ने दशकों की मेहनत, लगन, अमनी गुटनिरपेक्षता के लिए, मजबूती के जरिए जो ताकत अति की थी और अमेरिका को सबसे बड़ी 25 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया था, राष्ट्रपति ट्रंप उस पर पानी कर रहे हैं। भारत को 50 फीसदी टैरिफ से अमेरिकी ने दबाव में लाने की रणनीति बनाई, लेकिन भारत दूरसे ध्वज पर रूस और चीन के साथ मिल गया।

उत्तरे समुद्र में 50 अनादेश, ब्रिक्स और एएससीओ के देश आ खड़े हुए। भारत के वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि भारत का ऑफरटेलिया और ओमान के साथ कानून का कारा भी ही होने जा रहा है। भारत की 50 अनादेश के साथ चीनी निर्यात की संभावनाओं को बाध भी नहीं जाती है। अमेरिका के साथ भी नवंबर तक व्यापार-समझौता होना लगभग तय है। भारत आगामी दो सालों के भीतर विश्व की तीसरी

सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। सवाल यह है कि ट्रंप को भारत से दिक्कत है अथवा रूस और चीन से?

भारत ने पलट कर अमेरिका पर कोई टैरिफ नहीं थोपा है। अमेरिकी कंपनियां भारत की सार्वजनिक और निजी कंपनियों से अरबों डॉलर के कारगर कर रही हैं। अमेरिकी सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे अफि कारी ने अमेरिका में मंदी की संभावनाओं को लेकर राष्ट्रपति को सचेत किया है। ऐसे में विरोधपूर्ण समाने आए हैं कि एक-तिहाई उद्योग पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ कारोबार कम क्यों किया जा रहा है? टैरिफ का कोई औचित्य है। क्योंकि रूस के साथ भारत, चीन के अलावा अमेरिकी और यूरोपीय देश भी तेल और गैस का घुरा कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप को आरोप लगाने की अमनी आदत को सुझाना चाहिए। उन्होंने अपने मन पर आरोप चरपा किया है कि वह अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहा है। दरअसल बदलते विश्व परिस्थिति में अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है। ऐसे संबंधों को सिर्फ टैरिफ तक सीमित कर देना ट्रंप और अमेरिका के लिए उन्मुखनासावक होगा। विश्व विश्व विशेषज्ञ भी मानते हैं कि देश के राष्ट्रपतियों ने दशकों की मेहनत, लगन, अमनी गुटनिरपेक्षता के लिए, मजबूती के जरिए जो ताकत अति की थी और अमेरिका को सबसे बड़ी 25 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया था, राष्ट्रपति ट्रंप उस पर पानी कर रहे हैं। भारत को 50 फीसदी टैरिफ से अमेरिकी ने दबाव में लाने की रणनीति बनाई, लेकिन भारत दूरसे ध्वज पर रूस और चीन के साथ मिल गया।

उत्तरे समुद्र में 50 अनादेश, ब्रिक्स और एएससीओ के देश आ खड़े हुए। भारत के वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि भारत का ऑफरटेलिया और ओमान के साथ कानून का कारा भी ही होने जा रहा है। भारत की 50 अनादेश के साथ चीनी निर्यात की संभावनाओं को बाध भी नहीं जाती है। अमेरिका के साथ भी नवंबर तक व्यापार-समझौता होना लगभग तय है। भारत आगामी दो सालों के भीतर विश्व की तीसरी

साथी पोर्टल के विरोध में बीज और उर्वरक विक्रेताओं का प्रदर्शन

सांवाददाता-गोरखपुर। भारत सरकार के रबी सीजन से लागू किए जा रहे 'साथी पोर्टल' के विरोध में गोरखपुर बीज-उर्वरक व्यापारी संघ मालगवा को दुकानें बंद रखकर विरोध 1 प्रदर्शन किया। जिले के बीज विक्रेताओं के साथ उर्वरक के विक्रेताओं ने शांतिपूर्ण मार्च निकाल कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ

के आह्वान पर जनपद की 1188 बीज विक्रेता, 1100 के करीब उर्वरक, 850 के करीब कृषि श्रमा रसायन विक्रेताओं ने सारथन की घोषणा की है। सभी भागीदारी विक्रेता अपनी दुकानें बंद कर मालगवा की सुबह 10 बजे पंडित गोविंद बल्लभ पंत पार्क में एकत्र हुए। उसके उपरान्त वे शांतिपूर्ण मार्च निकाल कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ

साथी पोर्टल के विरोध में बीज और उर्वरक विक्रेताओं का प्रदर्शन

अदालती नोटिस

सम्मान बरजर इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जापो 200 ई0)

अपील संख्या-1125/24

प्रारस्थानक संख्या-C2024/1000001125

ग्राहक 207 उ0प्रारस्थानक-2006

अदालत-न्यायालय-श्रीमान आयुक्त महोदय बस्ती मजिस्ट्रेट बस्ती जिला-बस्ती

ध्रुव चन्द्र

नाम

दीपक त्रिपाठी आदि

1-दीपक त्रिपाठी पुत्र राजेंद्र प्रसाद

2-पुष्पा त्रिपाठी पत्नी राजेंद्र प्रसाद

8-अरविन्द कुमार 4-संजय कुमार

मुनियम सुबुन्द प्रसाद 5-श्रीमती कोकिला देवी पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद

8-जनार्दन प्रसाद 7-कृष्ण चन्द्र

8-अशोक कुमार पुत्रगण रामनिजल

9-अशोक कुमार पुत्र त्रिगुणी नारायण

साकिनगाम बानन बन्तजोशी तथा मसिना

परगना बांसी पूरव तहसील बस्ती जनपद सिद्धार्थनगर।

विश्ववीरगण प्रथम वर्ग

10-माया देवी पत्नी मुनियम साकिन

जमुनी तथा असराम 11-कनुला

देवी पत्नी रामरक्षा उर्फ रामरक्षा 12-

मोतीलाल पुत्र हिरकू (मूक) जरिये

बारिखान 12/1 नरेश 12/2 महेश

12/3 दिनेश 12/4 सुरेश पुत्रगण

मोतीलाल 12/5 सावित्री पत्नी

मोतीलाल 13-रामफेद 14-रामरक्ष

15-उत्तरवीर 16-रामचन्द्र 17-

गणेश पुत्रगण गंगापाल 18-विनय

19-विपुल पुत्रगण धर्मराज 20-

दुर्गावती पत्नी वमरका 21-श्रीमती

भनकी उर्फ ज्योत्सना पत्नी रंजीत

कुमार (मूक) जरिये वारिसा 21/1 सुरेश

21/2 राममिलन 21/3 राकेश

पुत्रगण रंजीत 22-श्रीमती प्रेमा देवी

पत्नी रामचन्द्र 23-कमला प्रसाद

पुत्र शिवरसम (मूक) जरिये वारिसा

23/1 कोकिला देवी पत्नी सुरेन्द्र

प्रसाद निवासीगण ग्राम बगगडोली

तथा मसिना परगना बांसी पूरव

तहसील बस्ती जनपद सिद्धार्थनगर।

अपील संख्या-1125/24

प्रारस्थानक संख्या-C2024/1000001125

ग्राहक 207 उ0प्रारस्थानक-2006

अदालत-न्यायालय-श्रीमान आयुक्त महोदय बस्ती मजिस्ट्रेट बस्ती जिला-बस्ती

ध्रुव चन्द्र

नाम

दीपक त्रिपाठी आदि

1-दीपक त्रिपाठी पुत्र राजेंद्र प्रसाद

2-पुष्पा त्रिपाठी पत्नी राजेंद्र प्रसाद

8-अरविन्द कुमार 4-संजय कुमार

मुनियम सुबुन्द प्रसाद 5-श्रीमती कोकिला देवी पत्नी सुरेन्द्र प्रसाद

8-जनार्दन प्रसाद 7-कृष्ण चन्द्र

8-अशोक कुमार पुत्रगण रामनिजल

9-अशोक कुमार पुत्र त्रिगुणी नारायण

साकिनगाम बानन बन्तजोशी तथा मसिना

परगना बांसी पूरव तहसील बस्ती जनपद सिद्धार्थनगर।

विश्ववीरगण प्रथम वर्ग

10-माया देवी पत्नी मुनियम साकिन

जमुनी तथा असराम 11-कनुला

देवी पत्नी रामरक्षा उर्फ रामरक्षा 12-

मोतीलाल पुत्र हिरकू (मूक) जरिये

बारिखान 12/1 नरेश 12/2 महेश

12/3 दिनेश 12/4 सुरेश पुत्रगण

मोतीलाल 12/5 सावित्री पत्नी

मोतीलाल 13-रामफेद 14-रामरक्ष

15-उत्तरवीर 16-रामचन्द्र 17-

गणेश पुत्रगण गंगापाल 18-विनय

19-विपुल पुत्रगण धर्मराज 20-

दुर्गावती पत्नी वमरका 21-श्रीमती

भनकी उर्फ ज्योत्सना पत्नी रंजीत

कुमार (मूक) जरिये वारिसा 21/1 सुरेश

21/2 राममिलन 21/3 राकेश

पुत्रगण रंजीत 22-श्रीमती प्रेमा देवी

पत्नी रामचन्द्र 23-कमला प्रसाद

पुत्र शिवरसम (मूक) जरिये वारिसा

23/1 कोकिला देवी पत्नी सुरेन्द्र

प्रसाद निवासीगण ग्राम बगगडोली

तथा मसिना परगना बांसी पूरव

तहसील बस्ती जनपद सिद्धार्थनगर।

विश्ववीरगण प्रथम वर्ग

10-माया देवी पत्नी मुनियम साकिन

जमुनी तथा असराम 11-कनुला

देवी पत्नी रामरक्षा उर्फ रामरक्षा 12-

मोतीलाल पुत्र हिरकू (मूक) जरिये

बारिखान 12/1 नरेश 12/2 महेश

12/3 दिनेश 12/4 सुरेश पुत्रगण

मोतीलाल 12/5 सावित्री पत्नी

मोतीलाल 13-रामफेद 14-रामरक्ष

15-उत्तरवीर 16-रामचन्द्र 17-

गणेश पुत्रगण गंगापाल 18-विनय

19-विपुल पुत्रगण धर्मराज 20-

दुर्गावती पत्नी वमरका 21-श्रीमती

भनकी उर्फ ज्योत्सना पत्नी रंजीत

कुमार (मूक) जरिये वारिसा 21/1 सुरेश

21/2 राममिलन 21/3 राकेश

पुत्रगण रंजीत 22-श्रीमती प्रेमा देवी

पत्नी रामचन्द्र 23-कमला प्रसाद

पुत्र शिवरसम (मूक) जरिये वारिसा

23/1 कोकिला देवी पत्नी सुरेन्द्र

प्रसाद निवासीगण ग्राम बगगडोली

तथा मसिना परगना बांसी पूरव

तहसील बस्ती जनपद सिद्धार्थनगर।

विश्ववीरगण प्रथम वर्ग

10-माया देवी पत्नी मुनियम साकिन

जमुनी तथा असराम 11-कनुला

देवी पत्नी रामरक्षा उर्फ रामरक्षा 12-

मोतीलाल पुत्र हिरकू (मूक) जरिये

बारिखान 12/1 नरेश 12/2 महेश

12/3 दिनेश 12/4 सुरेश पुत्रगण

मोतीलाल 12/5 सावित्री पत्नी

मोतीलाल 13-रामफेद 14-रामरक्ष

15-उत्तरवीर 16-रामचन्द्र 17-

गणेश पुत्रगण गंगापाल 18-विनय

19-विपुल पुत्रगण धर्मराज 20-

दुर्गावती पत्नी वमरका 21-श्रीमती

भनकी उर्फ ज्योत्सना पत्नी रंजीत

कुमार (मूक) जरिये वारिसा 21/1 सुरेश

21/2 राममिलन 21/3 राकेश

पुत्रगण रंजीत 22-श्रीमती प्रेमा देवी

पत्नी रामचन्द्र 23-कमला प्रसाद

पुत्र शिवरसम (मूक) जरिये वारिसा

23/1 कोकिला देवी पत्नी सुरेन्द्र

प्रसाद निवासीगण ग्राम बगगडोली

तथा मसिना परगना बांसी पूरव

तहसील बस्ती जनपद सिद्धार्थनगर।

कृषि मंत्री ने अयोध्या के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, पीड़ितों का सुना दर्द, बांटी राहत सामग्री

सांवाददाता-अयोध्या। प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वह कंदौली तहसील के दोरी माझा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत सामग्री वितरित की। मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक किताबें कि माजपा की योगी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रभावित परिवारों को राशन किता उपलब्ध कराई जा रही है। इतना समझा दिया गया है कि 15 से 20 दिन तक उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिफॉर्म इंसानों के लिए ही नही बल्कि महेशियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। चारा और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

अयोध्या की बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, पीड़ितों का सुना दर्द, बांटी राहत सामग्री

सांवाददाता-अयोध्या। प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वह कंदौली तहसील के दोरी माझा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत सामग्री वितरित की। मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक किताबें कि माजपा की योगी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रभावित परिवारों को राशन किता उपलब्ध कराई जा रही है। इतना समझा दिया गया है कि 15 से 20 दिन तक उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिफॉर्म इंसानों के लिए ही नही बल्कि महेशियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। चारा और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

अदालती नोटिस

सम्मान बरजर इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जापो 200 ई0)

अपील संख्या-1125/24

प्रारस्थानक संख्या-C2024/1740001081

ग्राहक 30 (1) उ0प्रारस्थानक-2006

अदालत-न्यायालय-श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला-बस्ती

हादक

बनाम

सरकार आदि

1. सरकार 2. रामफेद 3. शिव प्रसाद

4. रामदीन 5. श्यामसुन्दर पुत्रगण

भगलत 6. राजेंद्र 7. योगेंद्र पुत्रगण

सहजोड़ 8. बहोरे पुत्र खोब्रन 9.

सवाई पुत्र बचान 10. गोविन्द 11.

रविन्द्र पुत्रगण बिहारी लाल 12.

श्रीमती लाली पत्नी बिहारी लाल 13.

रामदास 14. बाबूराम पुत्रगण

रामअचल साकिनान मौजा महोपुर

तथा दुधखरा परगना नगर पूरव

तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेरी 17-09-2025

बाजेह हो कि ने आपके

नाम एक नालिस बाबत दापर की है।

लिहाजा आपके हुम होला है कि आप

बतारीख 17 माह 09 सन 2025 ई0

बवत 10 बजे दिन

बमुकाम असलतन या माफक वकील के

साथ कोहो के मुकदमे के हालत से करार

वाकई किया गया हो और जो कुल उमर

अहम मुतलिका मुकदमा जबाब दे सके

या जिसके साथ कोई और सखा हो जो कि जबाब ऐसे

सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही

दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख

जो आपके इजहार के लिये मुकरर है

वारे इन्फिसाल कर्तुस् मुकदमा के तजवीज हुई है

और आपको लाजिम है कि उसी रोज

जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी

जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते

हों पेश करें। आपको इतिला दी जाती है कि अगर

बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगेर

एल एंड टी व टाटा कंस्ट्रक्सी का कार्यकाल बढ़ा, अब तक 1400 करोड़ खर्च, 200 करोड़ से बर्नी गैलियां



सांवाददाता-अयोध्या। अयोध्या विश्व श्रीमान जन्मसूचि में बन रहे भव्य मन्दिर निर्माण कार्य की 6 मी गति को देखते हुए एल एंड टी व टाटा कंस्ट्रक्सी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब वे दोनों कंपनियां मार्च 2026 तक काम करेंगी। जबकि, पहले इनका कार्यकाल सितंबर 2025 तक तय था। राम मन्दिर नवम निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मन्दिर के शिखर पर पत्थरों का काम फहराने की तिथि 25 नवंबर प्रस्तावित है। आज होने वाली भवन निर्माण समिति व श्रीमान जन्मसूचि मंत्री क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में इस पर औपचारिक फैसला हुआ है। अब तक मन्दिर निर्माण पर करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इनमें से 1100 करोड़ रुपये का भुगतान

अयोध्या दीपोत्सव में बनेगा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगी रामनगरी

सांवाददाता-अयोध्या। उत्तराखण्ड अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। पैंटन विभाग द्वारा सरसू तद, राम की पैदल सहित अन्य वाटों पर दीपों की शृंखला से अलंकिता दृश्य प्रस्तुत किया जाएगा। रामनगरी का दीपोत्सव एक बार फिर नया ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। पैंटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि विभाग की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। अयोध्या में 2017 से भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इसे बरकरार रखते हुए दीपोत्सव में ही सरसू नदी पर सबसे बड़े दीप जलाने व सबसे बड़े आरती समारोह का आयोजन होगा। इस वर्ष 26 लाख से अधिक दीपों के साथ गिनीज

वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। उत्तराखण्ड अयोध्या में दीपोत्सव केवल अयोध्या के संस्कृतिक वैभव को ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर इसकी महत्वा को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्रभा प्रतिष्ठा को बहा दूरेसे दीपोत्सव को भव्यता और दिव्यता से मानने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राम की पैदल सहित अन्य वाटों पर इस बार 26 लाख से अधिक दीपों को जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं सरसू तद पर अब तक की सबसे बड़ी दीपोत्सव का आयोजन भी होगा, जिसमें 1100 से अधिक धर्माचार्य, संत-महात्मा और नगरवासी शामिल होंगे। आयोजन से तीन दिन पहले से श्रद्धांजलि श्रुति शुरू होगी। गिनीज मानकों के अनुसार डिजाइन आदि

अदालती नोटिस

इस्तराफ नजरिया अदालत- श्रीमान सिविल जज (सीओडि) महोदय बस्ती जिला-बस्ती

उत्तराधिकार प्रारस्थानक सं 197/2025

दलजीत गुप्ता उम लगमण 38

बर्ष पुत्र स्व 20 रामसूरत गुप्ता 2

नरजीत गुप्ता उम लगमण 39 वर्ष

पुत्र स्व 20 रामसूरत गुप्ता 3 सिरपती

देवी उम लगमण 69 वर्ष पत्नी स्व 20

रामसूरत गुप्ता निवासीगण ग्राम

बड़िया बुजुर्ग पोस्ट हथियागढ़ तथा

कडर परगना बस्ती पूरव तहसील व

जिला बस्ती

तारीख पेरी 15-10-2025

प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा-372

भारीय उत्तराधिकार

अभिनियम-1925

दरखास्त मुसुमा

बाबतें हुसुल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा

व विवालत हाय दरखास्त मुसुमा

मुसुमा अपने मजुबिज एक 7

सन 1889 ई0 कर्कद

हरगाह मुसुमा ने

दरखास्त हुसुल सर्टीफिकेट गुजारी

और तारीख माह सन 10 ई0 वारसे

समाप्त दरखास्त के मुकरर हुई है।

लिहाजा वह इस्तेहार जारी किया

जाता है कि किसी को निमत के

उज हो या असालतन या कवलतन

वस्त 10 जेबे सुबह अलगत सिविल

जज (सीओडि) बस्ती बतारीख पेरी

15-10-2025 मुकरर हाजिर होकर

उज अपना पेश करें। दरसूरत

इनकाजिले तारीख मजकूर के फिर

उज किसी का नुन न जयेगा और

हुम मुनासिब निमत दरखास्त